

संपादकीय

सुरक्षाबलों में असुरक्षा

साथी जवानों की हत्या से उठे सवाल

जम्मू-कश्मीर स्थित कठुआ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्वोरिटी फोर्स की ड्यूटी पर तैनात एक हिंसक साथी द्वारा चार जवानों की हत्या करने की घटना ने सुरक्षा बलों के भीतर छिपे खतरों की डरावनी तस्वीर उकेरी है। बताया जाता है कि सीआईएसएफ् के एक हेड कॉन्स्टेबल ने अपनी सर्विस ए-के-47 से गोलीबारी करके इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया। बताते हैं कि इस वाक्ये में कार्यस्थल पर अपने छोटे बच्चे को लेकर आने से शुरू हुई बहस कालांतर हिंसक टकराव में बदल गयी। विगत में भी मानसिक द्रढ़ से गुजर रहे सुरक्षा बलों के जवानों के हिंसक प्रतिरोध के मामले सामने आए हैं। ये घटना बताती है कि सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी समस्याओं के निपटारे के लिये मजबूत सिस्टम बनाने की सख्त जरूरत है। निस्संदेह, यह घटना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में काम करने की स्थितियों पर भी प्रश्न उठाती है। दरअसल, दूर-दराज के इलाकों में तैनात जवानों को लंबी और अनियमित ड्यूटी, परिवार से जुड़ी मुश्किलों तथा घर से लंबे समय तक दूर रहने जैसी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी तनाव से गुजर रहे सुरक्षाकर्मों के व्यवहार व मानसिक स्थिति पर संवेदनशील ढंग से नजर रखने की जरूरत होती है। यह संकेत इसलिए भी बड़ा है क्योंकि सुरक्षा कर्मियों का अनिवार्य रूप से हथियार रखना ड्यूटी का हिस्सा है। जिसके चलते मामूली विवाद के घातक रूप लेने की आशंका लगातार बनी रहती है। इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि हर छोटा-मोटा विवाद हिंसक रूप में बदल ही सकता है। लेकिन ऐसे संकेतों पर समय रहते ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि किसी दुखद घटना को टाला जा सके। निस्संदेह, केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों में ऐसे दुखद हादसों को टालने हेतु, जवानों की शिकायतों के समाधान के लिये

प्रभावी तंत्र और असरदार निगरानी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों में हथियारों को लेकर सुरक्षा उपाय और आसानी से उपलब्ध मनोवैज्ञानिक मदद, बचाव की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। निस्संदेह, किसी भी सुरक्षाबल में जवानों का अनुशासित होना, अपरिहार्य शर्त है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिये जवानों का हदरम शस्त्रों से लैस होना भी लाजिमी है। ऐसे में निगरानी व किसी भी टकराव को टालने के लिये उपायों को लेकर गंभीर पहल होनी चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व गृह मंत्रालय की एक टास्क फोर्स ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कुछ जवानों द्वारा अपने साथियों की हत्या करने के मुख्य कारणों की पहचान की थी। जिसमें उल्लेख किया गया है कि कठोर सेवा शर्तें, छुट्टी मिलने में देरी-विशेषकर परिवार में आपात स्थिति के समय, आलोचना, ऊप्रीडन पर प्रतिक्रिया तथा साथियों के अनुचित व्यवहार के कारण हिंसक प्रतिक्रियाएं बढ़ी हैं। कठुआ की घटना की जांच में भी यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या इस मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। यह दुखद है कि कि देश के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले देश के एक प्रमुख सुरक्षा बल ने अपने चार जवानों को असमय खो दिया है। निस्संदेह, उनकी मौत के लिये जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में किसी सशस्त्र बल के भीतर का मनमुटाव कभी इतने घातक परिणामों तक न पहुंच पाये। दरअसल, वक्त बदला है तो रोजगार के अवसर सिमटने के चलते उच्च शिक्षा हासिल युवा इन सुरक्षा बलों में भर्ती हुए हैं। जिंदगी में सुनहरे सपने लिये जब वे इन सुरक्षा बलों में आते हैं तो कठोर अनुशासन व सख्त नियमों के साथ साम्य नहीं बैठा पाते। वहीं सुरक्षा बलों का ढांचा पुराने ढर्रे पर चल रहा है, जो नई पीढ़ी की बदलाव की आकांक्षाओं के साथ तालमेल बैठता नजर नहीं आता है। फलतः जवानों की अपने अधिकारियों से अनेक मुद्दों पर वैचारिक भिन्नता हो सकती है। निस्संदेह, कठोर अनुशासन सुरक्षा बलों की अपरिहार्य शर्त होती है, लेकिन आज की पीढ़ी में पुरानी पीढ़ी जैसा धैर्य और सहनशीलता नजर नहीं आती है। जो कालांतर बड़े अधिकारियों के सख्त अनुशासित व्यवहार में बाधक होता है। निस्संदेह, देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के स्वरूप को बदलते वक्त की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने की जरूरत है।

डॉ. रितु सारस्वत

आर्थिक सलाकार परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को बंद करने और चीन की जनसंख्या नीति से सबक लेने की भी सिफारिश की है। हालिया ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6’ के आंकड़े भी निम्न प्रजनन दर की स्थिति की ओर संकेत करते हैं।

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने ‘द घोस्ट ऑफ़ पॉपुलेशन पास्ट : हाउ पॉपुलेशन कंट्रोल परसिस्ट्स इन इंडिया’ नामक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1 की प्रजनन दर जरूरी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दें तो राष्ट्रीय प्रजनन दर 1.6 रह जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण को सरकारी नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में देखना प्रासंगिक नहीं है। साथ ही, परिवार नियोजन की नीतियों को स्वास्थ्य, बच्चों के बीच अंतर रखने और व्यक्ति की निजी पसंद के अनुरूप रखने की बात कही गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को बंद करने और चीन की जनसंख्या नीति से सबक लेने की भी सिफारिश की। हालिया ‘राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6’ के आंकड़े भी अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निम्न प्रजनन दर की स्थिति की ओर संकेत करते हैं।

अमूमन यह समझना सहज नहीं है कि आखिर यह प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) इतना महत्वपूर्ण क्यों है और मूल रूप से यह है क्या। इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न सहज उत्पन्न होगा कि 2.1 यानी एक महिला 2.1 बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? इसे समझने के लिए पहले प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर, दोनों को समझना होगा।

प्रजनन दर का सीधा अर्थ है कि एक महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। वहीं, प्रतिस्थापन स्तर वह स्थिति है, जिसमें एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से संख्या के स्तर पर लगभग स्वयं को प्रतिस्थापित कर सके। सामान्यतः कम मृत्यु दर वाली आबादी में यह स्तर 2.1 बच्चे प्रति महिला माना जाता है। यानी 2.1 का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक महिला के 2.1 बच्चे हों, बल्कि यह पूरी आबादी में महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए

विवेक शर्मा

सूचना बताती है कि क्या हुआ, जबकि समझ यह जानने की कोशिश करती है कि क्यों हुआ, उसका असर किस पर पड़ेगा और उसके पीछे की तस्वीर क्या है। हमारे पास सूचना ज्यादा है, लेकिन समझने के लिए समय और धैर्य कम है।

सुबह आंख खुलते ही मोबाइल सामने होता है। रात में क्या हुआ, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में किसने क्या कहा, सब कुछ चंद पलों में पता चल जाता है। फिर भी दिन चढ़ने के साथ यह भरोसा नहीं बढ़ता कि हमें दुनिया पहले से ज्यादा समझ में आ रही है। उल्टे, कई बार लगता है कि खबरें बढ़ रही हैं और समझ सिकुड़ रही है।

कभी खबर के लिए अखबार का इंतजार होता था। अब खबरें इंजार नहीं करतीं। वे लगातार हमारे दरवाजे पर दस्तक देती रहती हैं। एक नोटिफिकेशन हटइए तो दूसरा सामने है। एक वीडियो खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद याद भी नहीं रहता कि सुबह पढ़ी गई दस खबरों में से कौन-सी बहान में महत्वपूर्ण थी।

यहीं सूचना और समझ का फर्क सामने आता है। सूचना बताती है कि क्या हुआ, जबकि समझ यह जानने की कोशिश करती है कि क्यों हुआ, उसका असर किस पर पड़ेगा और उसके पीछे की तस्वीर क्या है। हमारे पास सूचना ज्यादा है, लेकिन समझने के लिए समय और धैर्य कम है।

सोशल मीडिया ने इस समस्या को और पेचीदा बना दिया है। किसी घटना की पूरी जानकारी सामने आने से पहले ही उसका वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ शब्दों का शीर्षक लोगों की राय बना देता है।



लेकिन आज के समय में यह अनुभव एक नए पायदान पर पहुंच गया है। आज किंडरगार्टन के बच्चे को स्कूल के जिम्मेजियम हॉल या प्लेग्राउंड में अपनी पहली बैलेंस-बाइक मिलती है। उन्हें हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण पहन कर ऐसी बाइक पर बैठना होता है, जो पैडल-फ्री होती है और उसे वे पैरों से आगे बढ़ाते हैं।

बच्चे ऑरेंज ट्रैफिक-कोन से बने गोलाकार रास्ते पर बाइक स्टार्ट और स्टॉप करते हैं, जबकि आसपास पीटी टीचर्स समेत दूसरे वयस्क उन्हें देखते और डायरेक्शन देते रहते हैं। ये शिक्षक बच्चों को बैलेंस, कोर स्टेबिलिटी, सीक्रेसिंग और बॉडी-अवेयरनेस सिखाते हैं। इस प्रक्रिया में हर स्टेप पिछले स्टेप पर आधारित होती है।

इस दौरान हर नर्वस चेहरे के साथ एक मुस्कराता

चेहरा भी था। हर चीख के साथ एक हंसी भी थी। सोच रहे हैं कि यह सब कहाँ हो रहा है? अमेरिका के 2 हजार से ज्यादा एलीमेंट्री स्कूलों ने बाइक राइडिंग को बच्चों की फिजिकल एजुकेशन का हिस्सा बनाया है।

अन्यथा इन बच्चों को भी उन्हें सिखाने के लिए किसी वयस्क या बड़े भाई-बहन का इंतजार करना पड़ सकता था। आठ लेसन वाले इस पाठ्यक्रम में बच्चों को धीरे-धीरे सिखाया जाता है। पहले वे सिर्फ बाइक के साथ चलना, सही साइज की बाइक पर सहज होना और फिर दोनों पैर उठा कर बैलेंस बनाना सीखते हैं। इसके बाद वयस्क पैडल लगाते हैं और स्ट्रूटेड पूरी तरह साइकिलिंग करते हैं।

कुछ स्कूल बच्चों को पैदल यात्रियों की सुरक्षा



बच्चों का औसत है।

यह स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि प्रजनन दर लंबे समय तक इसके नीचे बनी रहती है तो आने वाली पीढ़ी का आकार धीरे-धीरे छोटा होने लगता है। इसका असर आगे चलकर आबादी की आयु संरचना तथा कार्यशील आबादी के आकार पर भी पड़ सकता है। ऐसे में जनसंख्या में एक संतुलन का होना महत्वपूर्ण हो जाता है।

हालांकि, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भारत की आबादी अब अचानक घटने लगेगी। कम प्रजनन दर का प्रभाव कुल आबादी में दिखाई देने में कई दशक लग सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में बड़ी संख्या में युवा आबादी मौजूद है और जनसांख्यिकीय जड़त्व के कारण कुछ समय तक आबादी बढ़ती रह सकती है। लेकिन यदि प्रजनन दर लंबे समय तक इसी तरह प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) से नीचे बनी रहती है तो आगे चलकर आबादी के आकार के साथ-साथ उसकी आयु संरचना में भी बड़ा बदलाव आएगा।

एनएफएचएस-6 के हालिया आंकड़े इस बदलाव की गंभीरता को समझने का एक संकेत देते हैं। अंडमान-निकोबार में कुल प्रजनन दर 0.9 तक पहुंच गई है, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी यह प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आने वाले समय में भारत के सामने केवल आबादी के आकार का नहीं, बल्कि वृद्ध होती आबादी, घटती कार्यशील आबादी और बदलती सामाजिक संरचना का प्रश्न भी खड़ा होगा। इसलिए यह ऐसा विषय है, जिस पर भविष्य की स्थिति का इंतजार करने के बजाय अभी से गंभीर

विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

आखिर प्रजनन दर में इस गिरावट के पीछे कारण क्या हैं? इसके कारणों को केवल जनसंख्या संबंधी आंकड़ों में तलाशना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे समाज में पिछले कुछ दशकों में आए उन बदलावों को समझना होगा, जिनका असर परिवार, विवाह, मातृत्व और बच्चों को लेकर हमारी सोच पर पड़ा है।

महिलाओं की शिक्षा इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा ने महिलाओं के सामने जीवन के विकल्पों का विस्तार किया है। उच्च शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य को लेकर निर्णय लेने की क्षमता ने महिलाओं के जीवन की प्राथमिकताओं को बदला है। विवाह और मां बनने का फैसला भी अब कई महिलाएं अपने जीवन की अन्य प्राथमिकताओं के ध्यान में रखते हुए लेने लगी हैं। लेकिन इसे केवल इस रूप में देखना उचित नहीं होगा कि महिलाओं के शिक्षित होने के कारण बच्चे कम हो गए। शिक्षा ने महिलाओं में अपने जीवन, करियर और भविष्य को लेकर आकांक्षाएं बढ़ाई हैं तथा परिवार और मातृत्व को लेकर निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत किया है। साथ ही, बच्चों की संख्या के बजाय उनके पालन-पोषण, शिक्षा और बेहतर भविष्य को महत्व देने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

ऐसे में प्रश्न केवल यह नहीं है कि महिलाओं की प्राथमिकताएं क्यों बदलीं, बल्कि यह भी है कि क्या परिवार और समाज ने महिलाओं के जीवन में आए इन बदलावों के अनुरूप स्वयं को बदला है? यही प्रश्न घटती प्रजनन दर को समझने के लिए आगे की चर्चा का आधार बनता है।

लेकिन महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और

निर्णय लेने की क्षमता में आए इस बदलाव को उस सामाजिक संरचना से अलग करके नहीं देखा जा सकता, जिसमें परिवार और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लंबे समय से मुख्यतः महिलाओं से जुड़ी रही है। जब महिलाओं के जीवन की प्राथमिकताएं बदलीं, तब यह सवाल भी सामने आया कि क्या परिवार और कार्यस्थल की व्यवस्था भी उसी गति से बदली? क्या महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के साथ परिवार और मातृत्व की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वैसी ही सामाजिक और संस्थागत सहायता मिली?

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में यह असंतुलन कई समाजों में विवाह और मातृत्व को लेकर नई पीढ़ी के निर्णयों को प्रभावित करता दिखाई देता है। समाजशास्त्री पीटर मैकडोनाल्ड की ‘जेंडर इक्विटी थ्योरी’ इस विरोधाभास को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार देती है। जब महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, लेकिन परिवार के भीतर बच्चों की देखभाल और चोरलू जिम्मेदारियों का बंटवारा उसी गति से नहीं बदलता, तब उनके सामने काम और परिवार के बीच एक नया तनाव पैदा होता है।

ऐसे में घटती प्रजनन दर को महिलाओं की बदलती आकांक्षाओं का परिणाम भर मानना अधूरा होगा; यह उस सामाजिक व्यवस्था का भी परिणाम हो सकती है, जो महिलाओं की नई भूमिका के साथ स्वयं को पूरी तरह बदल नहीं पाई। जनसंख्या को लेकर दुनिया की चिंता अब एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। ‘ऑन द कस्प : प्रेम पॉपुलेशन बूम टू बस्ट’ इस बदलाव को एक सवाल के सामने रखती है—‘फ्रॉम टू मेनी टू टू फ्यू?’ यानी बहुत अधिक से बहुत कम की ओर? यही सवाल भारत के लिए भी अब महत्वपूर्ण हो जाता है।

घटती प्रजनन दर के पीछे जिन सामाजिक बदलावों की भूमिका है, उन्हें समझना और उनके अनुरूप परिवार तथा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है। बच्चों का जन्म और पालन-पोषण केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानने वाली सोच को बदलना होगा। वरना आने वाले समय में वृद्ध होती आबादी का एक बड़ा वर्ग हमारे सामने होगा, जिसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पर्याप्त कार्यशील आबादी नहीं होगी। यह स्थिति किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं होगी।

लेखिका समाजशास्त्री एवं स्तंभकार हैं।

सूचनाओं की सुनामी में सिकुड़ती समझ



देखते ही देखते एक धारणा सच जैसी लगने लगती है। बाद में अगर कोई दूसरा तथ्य सामने आए तो उसे स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि राय पहले बन चुकी होती है।

वायरल होना सत्य की गारंटी नहीं है। लाखों लोगों तक पहुंची कोई पोस्ट भी गलत हो सकती है और किसी जरूरी तथ्य को शायद ही कोई साझा करे। डिजिटल दुनिया की विडंबना यही है कि जो बात सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो।

इसका एक कारण हमारी अपनी आदत भी है। हम वही देखना पसंद करते हैं जिससे सहमत होना आसान हो। सोशल मीडिया भी हमारी पसंद पहचानकर उसी तरह की सामग्री बार-बार सामने लाता है। धीरे-धीरे एक ऐसा घेरा बन जाता है जिसमें अपनी राय की पुष्टि तो खूब मिलती है, लेकिन उससे अलग सोचने वाले तथ्य कम दिखाई देते हैं। फिर हमें लगता है कि दुनिया

भी वही सोच रही है जो हम सोच रहे हैं। यह बात महज सोशल मीडिया की नहीं रह जाती। लोकतंत्र में सहमतति स्वाभाविक है, लेकिन असहमति के लिए साझा तथ्य भी जरूरी हैं। यदि हर व्यक्ति अपनी-अपनी सूचनाओं की दुनिया में बंद हो जाए तो बहस बहुत होगी, संवाद कम। अपनी बात कहने की आजादी जितनी जरूरी है, दूसरे की बात सुनने का धैर्य भी उतना ही जरूरी है।

ऐसे समय में पत्रकारिता की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है। जब हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है और कोई भी घटना कुछ ही क्षण में दुनिया के सामने पहुंच सकती है, तब असली काम सिर्फ सूचना देना नहीं, बल्कि उसकी पड़ताल करना, तथ्य अलग करना और घटना को संदर्भ में रखना है। हर वायरल विषय महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए पत्रकारिता की लोकप्रियता के पीछे भागने के बजाय सार्वजनिक महत्व को देखना होगा।

सिखाने के लिए दूसरे कार्यक्रमों से भी जुड़ते हैं। हममें से कई लोगों ने यह सीन देखा होगा, जब एक यंग-मदर अपने बच्चे को प्रेम में लेकर किसी बिल्डिंग से निकलती है और सड़क पार करने की कोशिश करती है।

जिस जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है, वहां उसका सामना तेजी से गुजर रहे साइकिल और अन्य सवारों के झुंड से होता है और उनमें से कोई भी ब्रेक लगाने के बारे में नहीं सोचता। आखिरकार जब थोड़ी जगह बनती है तो वह दौड़कर सड़क पार करती है। उसे भरोसा नहीं होता कि ये राइडर्स जेब्रा क्रॉसिंग के नियमों का पालन करेंगे और उन्हें बच्चे समेत सड़क पार करने देंगे। ऐसी घटना गंभीर सुरक्षा मसलों को बिल्कुल सटीकता से सामने लाती है।

यह अतिरिक्त सबक डिफ्रेंटली-एबलड बच्चों के लिए बहुत काम का होता है। मसलन, सिपटल के एक स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि सड़क कैसे पार करें, कैसे ड्राइवर्स से आई-कॉन्टेक्ट बनाएं और यदि कोई असुरक्षित व्यवहार कर रहा है तो कैसे पहचानें। वहां के टीचर कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आजादी और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करते हैं- ठीक वही एहसास, जो हमें पहली बार पिता या बड़े भाई के सहारे के बिना बाइक चलाने पर हुआ था।

फंडा यह है कि बाइक-राइडिंग धीरे-धीरे स्पोर्ट्स क्लास में बास्केटबॉल खेलने जैसी बेसिक स्किल बनती जा रही है। लेकिन इस तथ्य को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि बाइकिंग लाइफ-लॉन्ग रिक्त है। और ऐसे सबक बच्चों के मन में तब भी बने रहते हैं, जब वे बाइक की उम्र से काफी आगे निकल जाते हैं।

कभी पिता जो काम सहज रूप से करते थे, स्कूल आज साइंटिफिकली कर रहे हैं



एन. रघुरामन

बचपन में आपकी जिंदगी का पहला सबसे बेहतरीन माइलस्टोन क्या था? हममें से ज्यादातर लोगों के लिए यह ट्राई-साइकिल चलाना और पैरेंट्स से ‘वेरी गुड’ सुनना रहा होगा। लेकिन जीवन के या किसी प्रोजेक्ट के अहम टर्निंग पॉइंट, अचीवमेंट या पड़ाव की सबसे अच्छी, क्लासिक और निर्णायक मिसाल वह होती थी, जब आप साइकिल चला रहे हों और पिताजी ने उसे पीछे से नहीं पकड़ा हो।

पीढ़ियों से हम बच्चों ने यह स्किल ड्राइव-वे में (अमीरों के बच्चों के लिए), साइड-वेज में (कालोनी में रहने वाले मिडिल क्लास के बच्चों के लिए) और मेरे जैसे अन्य बच्चों (यदि आम आदमी के बच्चे हैं तो) ने चॉल के आसपास की गलियों में सीखी है।

आमतौर पर बड़ा भाई-बहन या पिताजी साइकिल को पीछे से पकड़े रहते थे, जब तक कि हम संतुलन बनाना नहीं सीख जाते। फिर एक दिन अचानक हमें पता चलता था कि वे पीछे से नदारद हैं और साइकिल चल रही है। उस दिन हम गिर भी सकते थे, साइकिल किसी चीज से टकरा सकते थे या हमें खरोंचें भी लग सकती थीं। लेकिन उसी दिन अचानक हमें लगता था कि हम ‘बड़े’ हो गए।

अपनापन

अपनेपन की भावना, रखना

हरदम आप।

सुख-दुख के साथी बनो,

कटे कष्ट संताप।।

मन के सच्चे भाव से, बनते हैं संबंध।
संबंधों की डोर में, चंदन-सी हो गंध।।

मात-पिता भाई-बहन, मिल बनते परिवार।
आपस में हो नेह जब, सुखद बने संसार।।

मन में हो विश्वास जब, जीवन भर का साथ।
नहीं टूटता उम्र भर, शुभाशीष जब माथ।।

‘सुष्मा’ शुभ संदेश है, सच्चे भाव सुमीत।
निज स्वार्थो से दूर हों, रखें सभी से प्रीत।।



सुष्मा प्रेम पटेल, रायपूर

सेवा संकल्प

सेवा सेतु : रोहित को घर बैठे मिल गया फटाका लाइसेंस

रायपुर। सेवा सेतु पोर्टल नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए घर बैठे आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के ग्राम मचंद्र निवासी रोहित कुमार साहू ने अस्थायी फटाका लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें समय पर लाइसेंस प्राप्त हो गया। इससे उनके समय और श्रम दोनों की बचत हुई। रोहित ने इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।



सक्षम योजना : हिमांशी पार्लर एवं बुटीक से बनी आत्मनिर्भर दुर्ग। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली दुर्ग जिले के ग्राम नवागांव (पुरदा) निवासी हिमांशी वर्मा ने अपनी मेहनत, लगन और शासन की सक्षम योजना से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता शर्मा के माध्यम से उन्हें सक्षम योजना की जानकारी मिली। आवेदन करने पर उन्हें 80 हजार रुपए की सहायता प्राप्त हुई। इसका उपयोग हिमांशी ने अपने पार्लर एवं बुटीक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया। लगभग एक वर्ष पहले शुरू किया गया उनका यह व्यवसाय अब धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रहा है। उनके पास प्रतिदिन 5 से 7 ग्राहक आते हैं। इससे उन्हें प्रतिदिन करीब 250 से 300 रुपये तक की आय हो रही है।



पीएम विश्वकर्मा योजना से बढ़ी नरेश की आजीविका
मानपुर। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के विकासखंड मानपुर के ग्राम सरोली निवासी नरेश कुमार चक्रधारी मिट्ठी के बर्तन, मूर्तियां एवं त्योहारों के अवसर पर मिट्ठी के दीये बनाने का कार्य करते हैं। उनके हुनर को आगे बढ़ाने और आजीविका को मजबूत करने में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उनके लिए उपयोगी साबित हुई है। योजना के अंतर्गत नरेश ने रसमड़ा सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त किया। योजना के अंतर्गत उन्हें विद्युत चाक प्रदान किया गया। विद्युत चाक मिलने से मिट्ठी के बर्तन, मूर्तियां एवं दीये बनाने के कार्य में गति आई है तथा कम समय में अधिक कार्य कर पाना संभव हुआ है। श्री नरेश कुमार बताते हैं कि विद्युत चाक मिलने के बाद उनके काम में सुविधा और तेजी आई है, जिससे वे अधिक मात्रा में मिट्ठी के बर्तन एवं अन्य सामग्री तैयार कर पा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से नरेश को मिला प्रशिक्षण और विद्युत चाक सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण की भावना का सार्थक उदाहरण है।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया सेवा संकल्प मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ

- एक छत के नीचे जुटे विशेषज्ञ डॉक्टर, 10 हजार लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य
- गंभीर बीमारियों से लेकर आंख, हड्डी, हृदय और कैंसर तक की जांच व उपचार सुविधा

रायपुर। सशक्त एमसीबी सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत चिरमिरी के पोड़ी स्थित मंगल भवन में दो दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य एवं नगर पालिक निगम चिरमिरी के महापौर रामनरेश राय की अध्यक्षता में हुआ। इस दो दिवसीय शिविर में जिलेवासियों को विभिन्न गंभीर एवं सामान्य बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिविर में 10 हजार लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार का लक्ष्य रखा

डेटा लेबलिंग और एआई में बलरामपुर ने रचा इतिहास; पहला कॉन्फिटिव डेटा एनोटेशन सेंटर स्थापित

श्रीकंचनपथ समाचार
रायपुर। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर-रामानुजगंज जिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा लेबलिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहाँ कॉन्फिटिव डेटा एनोटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के शिक्षित ग्रामीण युवाओं और स्व-सहायता समूह की

महिलाओं को एआई आधारित अत्याधुनिक रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है। कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज और प्रिन्मा एआई के बीच इस सेंटर की स्थापना के लिए एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी, प्रिन्मा एआई के सीईओ डॉ. श्रीराम अय्यर, सीओओ अमिताभ राय



चौधरी, सीटीओ विनीत कुमार झा तथा स्व-सहायता समूह की सदस्य सपना व अनुजा प्रमुख रूप से उपस्थित रहें। पायलट चरण के तहत बलरामपुर में 10 सीटों का सेंटर शुरू होगा, जिसमें एक समर्पित प्रशिक्षक और गुणवत्ता पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। चर्यनित प्रतिभागियों को एआई साक्षरता, डिजिटल कौशल, डेटा लेबलिंग, इमेज एवं ऑब्जेक्ट टैगिंग, वर्गीकरण, सत्यापन और गुणवत्ता समीक्षा का

व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की पहचान, छंटनी और चयन एक संरचित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 12वीं उत्तीर्ण और स्नातक सदस्यों वाले स्व-सहायता समूहों का बड़ा दायरा है जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने में दक्ष हैं। यह केंद्र दीर्घियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा तथा संबल प्रदान करेगा।

कृषि क्षेत्र में नवाचार की असीमित संभावनाएं स्टार्टअप्स के लिए आगे आएंगे युवा : कृषि मंत्री

श्रीकंचनपथ समाचार
रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि युवाओं को कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध असीमित संभावनाओं को तलाश कर स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए और एक नई सोच के साथ देश के विकास को नई गति प्रदान करना चाहिए।



श्री नेताम ने कहा कि मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया एवं रिकल इंडिया जैसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से नवाचार एवं स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी निपुण जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप एवं लघु मध्यम उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित कर रही है। कृषि मंत्री श्री नेताम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से आयोजित छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

श्री नेताम ने यूथ कॉन्क्लेव 2026 के भव्य एवं सफल आयोजन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल एवं उनकी

टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी एवं संचालक कृषि राहुल देव भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। अध्यक्षता कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। श्री नेताम ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी द्वारा नवनिर्मित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का अवलोकन भी किया तथा वहां उपलब्ध अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर यूथ कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ नवाचारी विचार प्रस्तुत करने वाले तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः एक लाख रुपये, पचहत्तर हजार रुपये एवं पचास हजार रुपये के

पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा युवाओं को नवाचारी व्यवसाय तथा स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए कई तरह सुविधाएं एवं अनुदान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को देखते हुए युवाओं को नवीन प्रौद्योगिकी एवं नवाचारी विचारों के साथ नए कृषि आधारित स्टार्टअप्स स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे कृषि के साथ - साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी बढ़ावा मिलेगा। कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने बताया

नशे के अवैध कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना जरूरी



श्रीकंचनपथ समाचार
रायपुर। नारकोटिक्स के मामलों में केवल आरोपियों तक पहुंचने के बजाय नशे के अवैध कारोबार से जुड़े पूरे वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नारकोटिक्स प्रकरणों की फाइनैशियल इन्वेस्टिगेशन पर एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेशभर से उप पुलिस अधीक्षक से सहायक उप निरीक्षक स्तर तक के 70 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के

निर्देशन में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए एडीजी नारकोटिक्स अमित कुमार ने कहा कि नारकोटिक्स के मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने के साथ ही उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान और जल्दी कर वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए प्रभावी और व्यापक विवेचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स पदार्थ कहां से आ रहा है, कौन इसकी आपूर्ति कर रहा है और इसे किस तक पहुंचाया जा रहा है, इन सभी पहलुओं पर फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंक स्थापित करते हुए वित्तीय जांच की जानी चाहिए।

उप पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स पारुल माथुर ने कहा कि एनडीपीएस प्रकरणों की विवेचना में विभिन्न संबंधित एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नशे के कारोबार से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यशाला के प्रथम सत्र में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग, रायपुर के डिप्टी डायरेक्टर प्रकाश चंद्र कान्हा ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि वित्तीय जांच के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि नशे के अवैध कारोबार में अवैध धन कहां से आ रहा है और उसे कहा निवेश किया जा रहा है। द्वितीय सत्र में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इन्डायरेक्ट टैक्सस एंड नारकोटिक्स, रायपुर के एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर श्री सलमान इमत्याज हुसैनी ने जीएसटी के विश्लेषण के माध्यम से अवैध धन और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन का पता लगाने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अनामिका जैन सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

लालमाटी में पहाड़ी कोरवा बस्ती के नौनिहालों को मिला बेहतर माहौल



श्रीकंचनपथ समाचार

सरगुजा। दूरस्थ पहाड़ी कोरवा बस्ती के नन्हे बच्चों को अब पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और नियमित गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल मिल रहा है। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत लालमाटी स्थित पहाड़ी कोरवा बस्ती में 11.69 लाख रुपये की लागत से नया आंगनबाड़ी भवन तैयार किया गया है। स्थायी भवन उपलब्ध होने से बच्चों को एक ही स्थान पर आंगनबाड़ी की विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की राह आसान हुई है। वहीं

माताओं और किशोरी बालिकाओं को भी पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं और जानकारीयें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की योजनाओं और विभागों अभिसरण के माध्यम से दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। लालमाटी की पहाड़ी कोरवा बस्ती में बना नवीन आंगनबाड़ी भवन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पहाड़ी कोरवा बस्ती में नवीन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण बोबी

जी राम जी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिसरण से 11.69 लाख रुपये की लागत से किया गया है। नया भवन मिलने से केंद्र की गतिविधियों के नियमित और व्यवस्थित संचालन के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध हुआ है। इससे बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार होने के साथ आंगनबाड़ी की सेवाओं को समुदाय तक पहुंचाने में भी सहायित हुई है। दूरस्थ बस्ती में ही केंद्र उपलब्ध होने से बच्चों और महिलाओं को विभिन्न सेवाओं एवं गतिविधियों से जोड़ना आसान हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। लालमाटी की पहाड़ी कोरवा बस्ती में नया भवन बनने से बच्चों के लिए नियमित गतिविधियों के संचालन की बेहतर व्यवस्था हुई है। अब उन्हें निर्धारित स्थान पर पोषण संबंधी सेवाओं के साथ प्रारंभिक शिक्षा और विभिन्न गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।

मात्र 1 घंटे में

गंजेपन से मुक्ति

COMPLETE FAMILY SALON

हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी

पहले बाद में

93009-11331

रंगोली कैलस के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0768-46060131

अनुप ट्रेडर्स

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता

लिंग रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

मो. 09826389666, 8839749539

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

ख़ास-ख़बर

नन्हे सितारों की प्रतिभा को मिला सम्मान



जशपुरनगर । जिला प्रशासन और ओपन लिक्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों में भाषा कौशल विकास, आत्मविश्वास और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित नन्हे सितारे कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता के 33 विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। नवीन सामुदायिक भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया गया। नन्हे सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक कविता प्रस्तुति, कहानी वाचन, स्मोकन इंग्लिश और स्पेलिंग बी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विकासखंडों में आयोजित प्रतियोगिताओं में 1036 स्कूलों के 5587 विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कहानी वाचन, कविता वाचन, स्पेलिंग बी और स्मोकन इंग्लिश चार विधाओं में विद्यार्थियों ने उसाहपूर्वक भाग लिया।

प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला।

कल से गांव-गांव में 'रिफॉर्म उत्सव', ग्राम सभा से बनेगा विकास का रोडमैप

रायपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में 02 अक्टूबर 2026 से 'रिफॉर्म उत्सव' के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जन योजना अभियान के साथ एकीकृत रूप से आयोजित होने वाले इस अभियान में ग्राम सभाओं को गांव के विकास की प्राथमिकताएं तय करने और योजनाओं पर सीधे संवाद का प्रमुख मंच बनाया जाएगा। ग्रामीणों से उनकी जरूरतों, विकास की कमियों, उपलब्ध संसाधनों और जरूरी कार्यों पर सुझाव लेकर इन्हें ग्राम पंचायत की आगामी विकास योजना में शामिल किया जाएगा। रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में वीबी-जीरामजी के तहत 125 दिवस रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, 375 अनुमेय कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण साथ साथ लखपति दीदी योजना, आजीविका गतिविधि जैसे विषयों पर ग्रामीणों से संवाद होगा। पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

पीएम स्वनिधि के लक्ष्य दो साल पहले पूरे करेगा छत्तीसगढ़, एक्शन-प्लान बनाने के निर्देश

ऋण के लंबित प्रकरण तत्काल निपटाने और हर पात्र स्ट्रीट वेंडर को योजना से जोड़ने के लिए निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नगरीय निकायों में पीएम स्वनिधि योजना में ऋण वितरण से लेकर डिजिटल लेन-देन के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। भारत सरकार से मिले लक्ष्यों को तय समय-सीमा से दो साल पहले पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी नगरीय निकाय इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाएंगे। बैंकों में लंबित ऋण प्रकरण तेजी से निपटाने के साथ ही पात्र पथ विक्रेताओं को योजना से जोड़ने शत-प्रतिशत डिजिटल सशक्तीकरण पर फोकस किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आर्म्सनिभर निधि) की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र पथ विक्रेता योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। योजना का मुख्य उद्देश्य पथ विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के सुलभ कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने नगरीय निकायों और बैंक



प्रतिनिधियों को आपसी समन्वय बढ़ाकर ऋण प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के ऋण वितरण की निकायवार और बैंकवार समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को निर्देशित किया।

प्रमुख सचिव बोरा ने मंत्रालय में आयोजित वर्युअल बैठक में सभी नगरीय निकायों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य समय-सीमा से दो वर्ष पहले हासिल करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर प्रभावी ढंग से अमल करने को कहा। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए निकायों और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया।

उन्होंने ऋण वितरण के साथ ही पथ विक्रेताओं के डिजिटल सशक्तीकरण पर भी फोकस करने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव बोरा ने बैठक में क्यूआर कोड वितरण, यूपीआई से डिजिटल लेन-देन और इस पर दिए जा रहे कैशबैक प्रोत्साहन की समीक्षा की। उन्होंने पथ विक्रेताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि की निगरानी समिति की बैठक में योजना को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाने राज्य और निकाय स्तर पर मानव संसाधन की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई। बैठक में क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति, प्रदेश में स्वच्छ एवं हाइजीनिक स्ट्रीट फूड हब की स्थापना और ऋण अदायगी की स्थिति की भी समीक्षा की गई। भारत सरकार को भेजे गए प्रस्तावों

छत्तीसगढ़

जहां कभी खौफ था, वहां है अब उम्मीद की रोशनी

दिल्ली से आए इंप्लुएंसेर्स ने देखी बदलते बस्तर की तस्वीर

श्रीकंचनपथ समाचार

केरलापेंदा में 21 साल बाद खुले श्रीराम मंदिर के द्वार, फिर से सुनाई देने लगी पूजा की घंटियां, जलने लगे आस्था के दीप

रायपुर। कभी जिन रास्तों पर कदम रखने से पहले लोग कई बार सोचते थे, जहां जंगलों के बीच बंदूक की आवाज और बारूदी सुरंगों का डर बस्तर की पहचान बन गया था, उन्हीं इलाकों में अब बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। यह बदलाव केवल सड़कों, सुरक्षा कैंपों या विकास कार्यों में नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है, जिन्होंने हिंसा का दौर अपनी आंखों से देखा है।



दिल्ली से आए 43 इंप्लुएंसेर्स ने बस्तर भ्रमण के दूसरे दिन सुकमा से जगरगुंडा और केरलापेंदा होते हुए, पूर्वाती तक का सफर किया। करीब 13 घंटे से अधिक चले इस सफर में उन्होंने बस्तर के उस चेहरे को करीब से देखा, जो लंबे समय तक देश के सामने नक्सल हिंसा की खबरों के जरिए ही आया। पुनर्वास केंद्र में मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों से संवाद से लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कहानी वाचन, कविता वाचन, स्पेलिंग बी और स्मोकन इंग्लिश चार विधाओं में विद्यार्थियों ने उसाहपूर्वक भाग लिया।

पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे 6 अधिकारी व कर्मचारियों का सम्मान

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। रक्षित केन्द्र दुर्ग स्थित प्रशासनिक भवन के दधीचि प्रशिक्षण हॉल में बुधवार को पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे 6 अधिकारी व कर्मचारियों के सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी व कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी व कर्मचारियों ने पुलिस विभाग में अपनी 35 से 40 वर्षों की सेवा अविधि के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों की



दीर्घकालीन सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उनके अनुभव विभाग के लिए उपयोगी एवं प्रेरणास्रोत हैं। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त के पश्चात भी विभागीय स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध रहेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात

द्वारा सभी सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों को शाल, श्रीपत्त एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उनके स्वस्थ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

कार्यक्रम के आयोजन में रक्षित केन्द्र दुर्ग एवं पुलिस कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों की सहभागिता रही। कार्यक्रम

के दौरान नीलकंठ वर्मा, रक्षित निरीक्षक दुर्ग रायकुमार गरेवाल, आंकिक शाखा, पुलिस कार्यालय एवं रक्षित केन्द्र दुर्ग के अधिकारी व कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों के परिजन उपस्थित रहे। दुर्ग पुलिस पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे सभी अधिकारी व कर्मचारियों को उनके दीर्घकालीन सेवाकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती है तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी व कर्मचारी: महिला निरीक्षक सावित्री धुवें, मुख्य लिपिक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग, एसएसआई अनिल सिंह, एसएसआई रामस्वरूप कुरेशिया, एसएसआई मानसिंह सोनवानी, प्रधान आरक्षक रामलखन सिंह, महिला प्रधान आरक्षक पुसु राजपूत।

गैर-आवासीय खेल अकादमी चयन ट्रायल : 144 खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर जिले में संचालित गैर-आवासीय फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी एवं एथलेटिक्स अकादमी में खिलाड़ियों के प्रवेश (नवीनीकरण एवं नवीन प्रवेश) के लिए आयोजित दो दिवसीय चयन ट्रायल के पहले दिन आज खिलाड़ियों के पंजीयन के साथ दस्तावेज, शारीरिक दक्षता और चिकित्सीय परीक्षण किया गया।

चयन ट्रायल के दूसरे दिन कल 1 अक्टूबर को पंजीकृत खिलाड़ियों के खेल कौशल का



परीक्षण किया जाएगा।

चारों गैर-आवासीय अकादमी में चयन के लिए कुल 144 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। विभागीय अधिकारियों एवं

भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण, नीरू और कयनान चेनाई ने रचा इतिहास

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एशियन गेम्स 2026 की ट्रैप मिक्स्ट टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय निशानेबाज नीरू और कयनान चेनाई को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

श्री चौधरी ने कहा कि नीरू और कयनान चेनाई ने अपने सटीक निशाने, शानदार तालमेल और अद्भुत एकाग्रता से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। एशियन गेम्स की ट्रैप मिक्स्ट टीम स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण

पदक जीतना भारतीय निशानेबाजी के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की यह स्वर्णिम सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन, समर्पण और जीत के दृढ़ संकल्प का परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर तिरंगा सबसे ऊपर लहराकर उन्होंने देश की खेल प्रतिभा और सामर्थ्य का शानदार प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री चौधरी ने नीरू और कयनान चेनाई के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर देश के लिए नई उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं दीं।

एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्व की प्रगति में लाए तेजी-कलेक्टर

मोहला । कलेक्टर तनुजा सलाम ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राज्य अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे, अपर कलेक्टर हेमंद भुआर्य, एसडीएम मोहला अमित नाथ योगी, एसडीएम मानपुर डीआर ध्रुव सहित सभी तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे की तहसीलवार प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सर्वे एवं पंजीयन कार्यों में आ रही समस्याओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

SAIRAM
Mobile Accessories

मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़कों की आवश्यकता है

7000415602

Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

चौरसिया ज्वेलर्स

आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता

बेन्वेक्स एवं ग्रहल उपलब्ध यहां उचित व्याज दर पर धिरोवी रखी जाती है

मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई

9827938211, 9827171332

CAR DECOR

House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories

Shop No.3 Nafish Tower,
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai

Mo.9300771925, 0788-4030919

K. Satyanarayan

**ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE**

Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture

Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 22964330

Shri Vijay Enterprises

Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.

Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला, मौत, जांच में जुटी पुलिस

जगदलपुर। जगदलपुर शहर से लगे नियानार बाईपास के पास देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती मृतकों की पहचान डमरूधर नाग और प्रदीप कश्यप के रूप में हुई शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परपा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हादसा किस वजह से हुआ और ट्रक चालक की स्थिति क्या थी, इसकी जांच की जा रही है। नियानार बाईपास के इस हिस्से में पहले भी कई बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां वाहनों की तेज रफ्तार और सड़क की स्थिति के कारण हादसों का खतरा बना रहता है। इससे पहले भी इस मार्ग पर हुए हादसे में लोगों की जान जा चुकी है। फिन्हाल देर रात हुए हादसे में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिसके बाद शव परिवजनों को सौंपा जाएगा।

कोरबा में सिगरेट को लेकर पान ठेले पर मारपीट

कोरबा। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र के कृष्णा नगर बस्ती में देर रात खिबड़े पान ठेले पर सिगरेट को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बताया गया कि राहुल शांडिल्य और उसका साथी दश निराला बाइक से किसी काम से गए थे। वापस लौटते समय दोनों कृष्णा नगर के पान ठेले पर रुके और कुछ सामान मांगा। तरुण साहू, देवेन्द्र सिंह और लाला वहां पहुंचे और सिगरेट मांगने लगे। सामान देने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। मारपीट में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद शहर की उन बस्तियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां देर रात तक पान ठेले और अन्य दुकानों पर सिगरेट, गुटखा, डिस्कोजल और चखना जैसी सामग्री उपलब्ध रहती है। स्थानीय स्तर पर देर रात तक ऐसी दुकानों के संचालन और वहां होने वाली गतिविधियों की निगरानी को लेकर चिंता जताई जा रही है।

नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा

रायगढ़। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृतिक जीवनकाल यानी अंतिम सांस तक कारावास से है। आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक अर्चना मिश्रा के मुताबिक, 11 दिसंबर 2021 की शाम नाबालिग अपनी सहेली के साथ गांव में शादी पर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी अकिल साय कोरवा (20) निवासी सहापानी, सीतापुर, जिला सरगुजा ने उसे रास्ते से जबरन खींच लिया और जंगल ले गया। वहां उसके साथ रेप किया।

सक्ती में चोरी की बाइक बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

सक्ती। सक्ती पुलिस ने गोमती अस्पताल के सामने से बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की हीरो एचएफ डिलक्स बाइकभी बरामद की है। जांच में आरोपियों के बाइक चोरी के साथ चोरी की बाइकों की खरीद-फरोख्त में शामिल होने की बात सामने आई है।

26 सितंबर को पीड़ित अपनी मां का इलाज कराने गोमती अस्पताल आया था। उसने अस्पताल के सामने बाइक खड़ी की थी। वापस लौटने पर बाइक गायब मिली। शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 412/2026 के तहत धारा 303(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और एसडीओपी डॉ. भुनेश्वरी पैकारा के निर्देश पर पुलिस टीम ने मुखबिरों से जानकारी जुटाई। करन कुमार कुर्से से पूछताछ में चोरी की बाइक बरामद हुई।

आगे की जांच में रेहान खान, नागेन्द्र कुमार पटेल और सोमनाथ सहिस के भी मामले में शामिल होने की

अवैध चाकू लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार

रायपुर। पुरानी बस्ती पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से लोहे का एक चाकू बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। 30 सितंबर को थाना पुरानी बस्ती की टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और अवैध हथियार रखने वालों की निगरानी एवं चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कैलाशपुरी ढाल, नया रोड, महाराजबंद तालाब के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में चाकू लेकर घूमता हुआ दिखाई दिया। युवक ने अपना नाम चंदन सेन (20), थाना अहिबारा, जिला दुर्ग बताया।इसके पास चाकू रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका।

तंत्र-मंत्र के नाम पर महिला से ठगी : अकाल मौत आने की बात बोलकर लिया 150 ग्राम सोना, आरोपियों की तलाश जारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर के गंज थानाक्षेत्र में फाफाडीह के जयलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में तंत्र-मंत्र और बीमारी ठीक करने का झांसा देकर महिला से करीब 150 ग्राम सोने के जेवर और १ हजार रुपए ठगने का मामला सामने आया है।

तीन आरोपी साधुओं के भेष में महिला के घर पहुंचे थे। उन्होंने बीमारी और आंखों की परेशानी ठीक करने के साथ परिवार की समस्याएं दूर करने का

भरोसा दिलाया। इसके बाद पूजा के नाम पर अलग-अलग समय में जेवर लेते रहे। घटना मार्च 2026 की बताई जा रही है। तीनों आरोपी साधु बनकर नैना परमार के घर के आसपास पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने महिला की बीमारी और आंखों से जुड़ी परेशानियों के बारे में ऐसी बातें बताईं, जिन्हें महिला ने अपनी निजी स्थिति से जोड़कर देखा।

उसे लगा कि साधुओं को उसके बारे में विशेष जानकारी है। इसके बाद



उन्होंने पूजा कराने की बात कही। पहली बार करीब 3 ग्राम की सोने की अंगूठी और 9 हजार रुपए लिए।

आरोप है कि हर 10-12 दिन में घर आकर पूजा के नाम पर जेवर मांगते रहे। महिला ने करीब सात बार में लगभग 150 ग्राम सोने के जेवर दे दिए। इनमें अंगूठी, चेन, हार, चूड़ियां और कंगन शामिल हैं। महिला के मुताबिक आरोपी उसे डराते थे कि अगर जेवर देने की बात किसी को बताई तो परिवार में बड़ी अनहोनी हो सकती है। परिवार के किसी

सदस्य की अकाल मौत तक होने की बात कही गई।

डर के कारण महिला ने पति और परिवार को कुछ नहीं बताया। 7 सितंबर से आरोपी दोबारा सोने-चांदी के जेवर और नकदी मांगने लगे। इसके बाद पति गंज थाने पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफधोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है।

ड्राय-डे से पहले 184 लीटर शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

रीक्रेट कमरों में छिपाकर रखी थी,शराब और वीयर बरामद



श्रीकंचनपथ न्यूज

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा के अकलतरा थाना पुलिस ने 2 अक्टूबर के शुष्क दिवस से पहले अवैध शराब बेचने की तैयारी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर के तहखाने और गुप्त कमरों से 184 लीटर शराब जन्ब की है। जब्त शराब की कीमत करीब 88 हजार 550 रुपए बताई गई है।

पुलिस के मुताबिक जब्त शराब में देशी प्लेन, मसाला, अंग्रेजी व्हिस्की और वीयर शामिल है। आरोपी की पहचान अकलतरा के वाई नंबर 12, गुम्फासीदास मोहल्ला निवासी टेकुलाल बंजारे (41) के रूप में हुई है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी ने शुष्क दिवस पर बेचने के लिए घर में शराब छिपाकर रखी है। सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपी के घर में छापा मारकर तलाशी ली। इस दौरान तहखाने और गुप्त कमरों से अलग-अलग ब्रांड की शराब बरामद हुई।

आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अकलतरा थाने में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) और 59(क) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शुष्क दिवस को देखते हुए जिले में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

ज्वेलरी दुकान की दीवार में छेदकर घुसे चोर, 5 लाख से ज्यादा के जेवर पार, जांच में जुटी पुलिस

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी के घनी आबादी वाले रामनगर स्थित श्रीलक्ष्मी विनायक ज्वेलर्स में मंगलवार 29 सितंबर की रात चोरों ने संधमारी की। बदमाशों ने बगल के खाली प्लाट की तरफ से दुकान की दीवार में मशीन से बड़ा छेद किया।

इसी रास्ते एक चोर दुकान के भीतर घुसा और सोने-चांदी के जेवर सज्जे। बाहर दो साथी निगरानी करते रहे। बुधवार 30 सितंबर सुबह करीब 10.30 बजे दुकान खुलने पर चोरी का पता चला। संचालक के मुताबिक करीब 3 किलो चांदी और एक तोला सोना चोरी हुआ है। चोरी गए माल की कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा है। दुकान से चंद



कदम की दूरी पर पुलिस चौकी होने के बावजूद रातभर हुई इस वारदात की भनक पुलिस को नहीं लगी। दीवार में छेद कर घुसे, कैमरे में नकाबपोश कारोबारी सुनील जैन की कर्मा चौक, रामनगर में 20 साल से दुकान है। मंगलवार रात 8 बजे वे दुकान बंद कर गए थे। बुधवार सुबह पहुंचे तो सामान बिखरा और फर्नीचर टूटा

कटरा जंगल में 1000 लीटर अवैध डीजल जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा में बलौदा-अकलतरा पुलिस ने कटरा जंगल से करीब 1000 लीटर अवैध डीजल जब्त किया है। यह डीजल एक पिकअप वाहन के पीछे बने लोहे के टैंकर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने डीजल परिवहन में इस्तेमाल पिकअप और उसके आगे चल रही आर्टिगा कार को भी जब्त किया है। जब्त वाहनों और डीजल की कुल कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों को कोर्ट भेजा गया है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन में अवैध डीजल भरकर हरदीबाजार रोड की ओर ले जाया जा रहा है। इसके आगे आर्टिगा कार चल रही थी। इस सूचना पर एसडीओपी अकलतरा डॉ. मेखलेंद्र प्रताप के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कटरा जंगल में घेराबंदी की। जांच के दौरान पिकअप में 1000 लीटर डीजल मिला, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है।

वाहन में सवार नरेश कुमार भारती, भीमसिंह गोंड और रामनरेश प्रजापति डीजल के वैध दस्तावेज नहीं



दिखा सके।

करीब 15 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस ने भीमसिंह गोंड के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए कीमत का पिकअप वाहन और करीब 1 लाख रुपए का डीजल जब्त किया। वहीं नरेश कुमार भारती के कब्जे से करीब 9 लाख रुपए कीमत की आर्टिगा कार बरामद की गई।

इस तरह पुलिस ने डीजल और दोनों वाहनों समेत करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बरामद डीजल को पिकअप के टैंकर में ही सीलबंद कर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया।

श्रीकंचनपथ न्यूज

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में 61 लाख 6 हजार 592 रुपए के ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि साइबर ठगी की रकम के लेन-देन के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया और बाद में रकम को क्रिप्टोकॉरेंसी में बदलकर उसके स्रोत को छिपाने का प्रयास किया गया। मामले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला गौदम थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान दिनेश (31), निवासी कृष्ण नगर, चौकी लक्ष्मण नगर, थाना भोजासर, जिला फलोदी (राजस्थान) के रूप में हुई है। पुलिस के चांदी से तस्कनीकी साक्ष्यों के



आधार पर राजस्थान में उसकी तलाश की और उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दंतेवाड़ा लाया गया। 30 सितंबर को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जिला जेल दंतेवाड़ा भेज दिया गया।

हारमपारा गौदम निवासी भूपेंद्र तेलामी (44) की रिपोर्ट पर ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के मामले में थाना गौदम में अपराध क्रमांक 27/2025 दर्ज किया गया था। मामले में कुल 61 लाख 6 हजार 592 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस ने धारा 318(4), 111(1)(3) बीएनएस और

66डी आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एनालिसिस और साइबर फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर साइबर फ्रॉड में शामिल आरोपियों और उनके बैंक खातों की जानकारी जुटाई गई। इसी जांच के आधार पर राजस्थान में आरोपी की पहचान हुई और पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार किया।

पुलिस के मुताबिक आरोपी बैंक खातों को किराए पर लेकर साइबर ठगी से प्राप्त रकम का लेन-देन करते थे। इसके बाद इस रकम को क्रिप्टोकॉरेंसी में बदलने का प्रयास किया जाता था, ताकि ठगी की रकम के वास्तविक स्रोत और अपराध से जुड़े साक्ष्यों को छिपाया जा सके।

11 दुकानदारों पर 11 हजार जुर्माना, 13 किलो प्रतिबन्धित प्लास्टिक जब्त

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम की स्वच्छता टीम ने व्यापार विहार और पुराने बस स्टैंड में दुकानों की जांच की। इस दौरान 11 दुकानों में प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और भंडारण पाया गया। निगम ने सभी 11 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 13 किलो प्रतिबन्धित प्लास्टिक जन्ब किया और कुल 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

पुराने बस स्टैंड से सतीश जायसवाल, जितेंद्र खबड़ा और मिली खबड़ा के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं व्यापार विहार से सूरज, बलराम, दिनेश, महेश, सौरभ मिश्रा, नरेश मंगवानी, ललित और प्रतीक पर कार्रवाई हुई। निगम ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि आगे प्रतिबन्धित प्लास्टिक का इस्तेमाल या बिक्री



करते पाए जाने पर और ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसके इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने व्यापारियों और लोगों से प्लास्टिक की जगह कागड़े, जूट या दूसरे पर्यावरण अनुकूल थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले, पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

खास-खबर



स्वच्छता दीर्घियों के योगदान का हुआ सम्मान'

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 'सेवा मेरा योगदान' पहल के माध्यम से जांजगीर-चांपा जिले में स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने के साथ स्वच्छता कर्मियों के योगदान को सम्मान दिया जा रहा है। नगर पंचायत सारागांव में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी-कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया, वहीं नगर पंचायत खरौद में स्वच्छता दीर्घियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करने के साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अभियान के दौरान नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने और कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने के लिए प्रेरित किया गया।



मुख्यमंत्री की पहल पर श्री-टोला को मिली रंगमंच और हाई मास्ट की सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप बुनियादी और सामुदायिक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत कुंजारा के आश्रित ग्राम श्री-टोला में ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। यहां दुर्गा पूजा स्थल पर हाई मास्ट लाइट स्थापित की गई है, वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विधायक निधि से 3 लाख रुपये की लागत से रंगमंच का निर्माण कराया गया है। रंगमंच और हाई मास्ट लाइट की सुविधा मिलने से गांव में सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हुई है।

राजनीतिक प्रकरण वापसी समिति ने 9 प्रकरणों की अनुशंसा की, 2 पर पुनर्विचार

समिति ने गैर राजनीति मामलों को किया अस्वीकृत

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी के संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रकरण वापसी समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि मनीष ठाकुर, गृह सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, डीजीपी अरूण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की



गई। जिसमें 8 लंबित प्रकरण शामिल थे, सभी मामलों में से 9 प्रकरणों की अनुशंसा की गई, 02 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए जिलों में भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त शेष मामलों को राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ ना पाते हुए उनको समिति ने अस्वीकृत कर दिया।

समिति ने अधिकारियों से पूर्व में अनुसंहित लंबित प्रकरणों, उनकी वर्तमान स्थिति तथा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बस्तर संभाग और आसपास के इलाकों में बारिश के चलते उत्पन्न होने वाली गंभीर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड ने अभूतपूर्व तत्परता दिखाई है। कंपनी ने युद्धस्तर पर संसाधन जुटाते हुए महज 48 घंटे के भीतर पुणे से चार अत्याधुनिक रेस्क्यू स्पीड बोट जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। प्रत्येक बोट लगभग 8 से 10 व्यक्तियों की वहन क्षमता वाली है, जिन्हें आपदा प्रबंधन के कड़े सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।

इन चारों स्पीड बोट को बुधवार 30 सितंबर को नारनार ग्राम पंचायत भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप द्वारा बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा को विधिवत रूप से चारों बोट सौंप दिया गया।

इस अवसर पर सांसद बस्तर महेश कश्यप ने एनएमडीसी प्रबंधन की सराहना की और कहा

बाढ़ आपदा में बचाव एवं राहत के लिए मिले 4 रेस्क्यू स्पीड बोट

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बस्तर संभाग और आसपास के इलाकों में बारिश के चलते उत्पन्न होने वाली गंभीर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड ने अभूतपूर्व तत्परता दिखाई है। कंपनी ने युद्धस्तर पर संसाधन जुटाते हुए महज 48 घंटे के भीतर पुणे से चार अत्याधुनिक रेस्क्यू स्पीड बोट जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। प्रत्येक बोट लगभग 8 से 10 व्यक्तियों की वहन क्षमता वाली है, जिन्हें आपदा प्रबंधन के कड़े सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।

इन चारों स्पीड बोट को बुधवार 30 सितंबर को नारनार ग्राम पंचायत भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप द्वारा बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा को विधिवत रूप से चारों बोट सौंप दिया गया।

इस अवसर पर सांसद बस्तर महेश कश्यप ने एनएमडीसी प्रबंधन की सराहना की और कहा

कि यह बाढ़ भीषण आपदा के रूप में सामने आई है। ऐसे विपदा के समय बचाव एवं राहत कार्य के लिए बेहतर संसाधन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्टील प्लॉट द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई नाव और राहत सामग्री के बावजूद जलभराव की विकरालता को देखते हुए अतिरिक्त संसाधनों की सख्त जरूरत थी। एनएमडीसी प्रबंधन से चर्चा होते ही पुणे से इन बोटों को तत्काल मंगाकर प्रशासन को सौंपना बेहद सराहनीय पहल है। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में भी प्रशासन के साथ निरंतर संवाद की बात कही।

कलेक्टर आकाश छिकारा ने एनएमडीसी की सक्रिय सहभागिता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सहयोग इस दिशा में बल प्रदान कर रहा है। वहीं नगरनार स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक प्रमोद कुमार ने बस्तर क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

उपयोग किया जाएगा।

वर्तमान में सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं

16,619 केंद्रों के जरिए ऑनलाइन

उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक अप्रैल

2025 से अब तक सेवा सेतु पोर्टल पर

54 लाख 23 हजार से अधिक आवेदन

प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण

किया गया है। प्रदेश में 28,450 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर के

माध्यम से भी 600 से अधिक शासकीय एवं व्यावसायिक सेवाएं

नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। एमओयू के बाद सेवा सेतु की

907 शासकीय सेवाओं की पहुंच सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटरों तक

भी विस्तारित होगी। इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों

के नागरिकों को अपने नजदीक ही अधिक सेवाएं प्राप्त करने की

सुविधा मिलेगी।

चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच हुआ एमओयू

युवाओं को रोजगार, नागरिकों को सुगम सेवाएं और आधुनिक कौशल से जोड़ना ही प्राथमिकताएं

■ नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उप अभियंताओं को मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र

■ सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं ऑनलाइन

■ नवा रायपुर में स्थापित होगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट



नागरिकों तक आसानी और समयबद्धता के साथ पहुंचें। वहीं युवाओं को सरकारी सेवाओं के साथ उद्योग, निजी क्षेत्र, उद्यमिता और कौशल आधारित रोजगार के लिए भी तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में उप अभियंता के पद पर चयनित युवा अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने नवनियुक्त अभियंताओं के अभिभावकों को भी बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर भविष्य के छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं का शहर है। यहां आधुनिक अधोसंरचना, गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं और

योजनाबद्ध विकास को निरंतर विस्तार दिया जा रहा है। नवनियुक्त अभियंताओं को इस आधुनिक शहर के निर्माण और विकास में योगदान देने का महत्वपूर्ण अवसर मिला है।

उन्होंने युवा अभियंताओं से कहा कि वे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रोजगार केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं हो सकती, इसलिए राज्य सरकार उद्योग, निजी क्षेत्र, उद्यमिता, स्टार्टअप और कौशल विकास के माध्यम से भी व्यापक अवसर तैयार कर रही है।

नई औद्योगिक नीति 2024-30के अंतर्गत अब तक 8 लाख 23 हजार

डिजिटल गवर्नेंस : चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन

सर्विस सेंटर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू

के माध्यम से सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध

नागरिक-केंद्रित सेवाओं को कॉमन

सर्विस सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी

जोड़ा जाएगा। इसी तरह कॉमन सर्विस

सेंटर पर उपलब्ध सेवाओं को सेवा सेतु से जोड़ा जाएगा। इससे

नागरिकों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता

कम होगी और अधिक सेवाएं उनके नजदीकी केंद्रों पर आसानी

से उपलब्ध हो सकेंगी। इन केंद्रों पर एकरूप ब्रांडिंग और

साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। केंद्रों पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं की

जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतिम

छोर तक शासकीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के

ग्राम स्तरीय उद्यमी नेटवर्क और सेवा सेतु केंद्रों का समन्वित

सेवा सेतु

उपयोग किया जाएगा।

वर्तमान में सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 907 सेवाएं

16,619 केंद्रों के जरिए ऑनलाइन

उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक अप्रैल

2025 से अब तक सेवा सेतु पोर्टल पर

54 लाख 23 हजार से अधिक आवेदन

प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण

किया गया है। प्रदेश में 28,450 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर के

माध्यम से भी 600 से अधिक शासकीय एवं व्यावसायिक सेवाएं

नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। एमओयू के बाद सेवा सेतु की

907 शासकीय सेवाओं की पहुंच सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटरों तक

भी विस्तारित होगी। इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों

के नागरिकों को अपने नजदीक ही अधिक सेवाएं प्राप्त करने की

सुविधा मिलेगी।

केबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नीति में किया संशोधन



श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी संशोधित नीति-2026 का कार्यांतर अनुमोदन किया गया।

संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मैरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। साथ ही, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अवशसकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए

अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था। मंत्रिपरिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाए तथा मानदेय निर्धारण में व्यास विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि एवं आकस्मिक अवकाश संबंधी प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 का अनुमोदन किया है। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

हनुमान अंश

मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितम्बर, 2026 को फिल्म 'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन में, फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाधरों को किए जाने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

अग्निवीरों को आरक्षण

पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

अंतराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर विशेष

वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार

हरिषित अग्रवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन वरिष्ठ जनों के सम्मान, सुरक्षा व आत्मविश्वास को बढ़ाने विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है। इससे वरिष्ठ जनों में न केवल आर्थिक स्थिरता आई है बल्कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर भी मिला है। समाज कल्याण विभाग वरिष्ठजनों के लिए वृद्धा पेंशन, पुनर्वास, तीर्थ दर्शन, आदि योजनाएं चला रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व व समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के दिशा निदेश पर इन योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है। इन प्रयासों से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और भवनात्मक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा

छत्तीसगढ़ शासन का लक्ष्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को समाज की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना भी है। पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, सहायक



और बसों के जरिए हजारों वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों तथा विधवा/परित्याक्त महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 यात्राओं के माध्यम से 10 हजार 694 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत भी पिछले एक साल में 28 हजार से अधिक श्रद्धालु लाभान्वित हुए हैं।

सहायक उपकरण

सहायक उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर अधिकतम 6900 रुपये तक के उपकरण जैसे

संचालित की जाती है। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अलग से किसी 'सैनियर सिटीजन कार्ड' की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड एवं अन्य वैध दस्तावेजों के माध्यम से आया और पात्रता का सत्यापन किया जाता है।

वृद्धाश्रम संचालन

बेसहारा और निराश्रित वृद्धजनों को आवास, भोजन, और सबल प्रदान करने के लिए राज्य में वृद्धाश्रमों का संचालन व वित्तीय सहायता दी जाती है। रायपुर सहित विभिन्न जिलों में 27 वृद्धाश्रम संचालित हैं जिनमें 675 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पेंशन योजनाएं

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बीपीएल एवं एसईसीसी वंचन समूह के वृद्धजनों को 500 रुपये प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 680 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है।

पैलिपेटिव केयर

गंभीर रूप से बीमार एवं बिस्तर पर आश्रित वृद्धजनों के लिए राज्य में 13 प्रशामक गृह संचालित हैं। वर्तमान में रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग, बालोद, रायगढ़ एवं बेमेतरा में 140 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। इन केंद्रों में निरंतर देखभाल, उपचार सहयोग और आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

सियान हेल्पलाइन

बुजुर्गों की विभिन्न समस्याओं, शिकायतों और आपातकालीन स्थिति के त्वरित निराकरण के लिए सियान हेल्पलाइन सेवा



सुविधाओं और सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सशक्त, संवेदनशील और समग्र सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित हो रहा है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन

योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को देश के 19 से ज्यादा तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया जाता है। विशेष ट्रेनों

के लिए प्रेरित किया गया।

दूसरे दिवस 29 सितंबर को 'छत्तीसगढ़ की नवाचार अर्थव्यवस्था का निर्माण'-स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी, निवेश एवं उद्योग के माध्यम से युवाओं का सर्वाधिकरण' विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई।

इसमें हेमन्त माथुर, सह-संस्थापक, थिंकपेरा, प्रदीप गोधुले, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर, सोमेश शर्मा, संस्थापक, ऑगटेक नेक्स्टेक्त्व, डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, अनुसंधान संचालक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा प्रो. हुलास पाठक, प्रमुख एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईजीकेवी आर-एबीआई ने सहभागिता की।

उद्यमियों की स्टार्टअप यात्राएँ सत्र में प्रियंक पटेल, संस्थापक, नुक्कड़ कैफे, अर्पित चौहान, संस्थापक, एरकी मोटर्स, एचएच सैफो, निदेशक, क्रॉपवे तथा डॉ. रविन्द्र दुबे, संस्थापक, फाइवोनेची लॉनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी यात्राएं साझा कीं।

कृषि, प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के परिप्रेक्ष्य' विषय पर चर्चा हुई। इसमें स्थानीय समस्याओं की पहचान, नवाचार आधारित समाधान, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहयोग तथा संस्थानत इन्क्यूबेशन के महत्व पर विचार साझा किए गए। प्रेरणादायी सत्र में युवाओं को रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने